नैक द्वारा प्रत्यायित श्रेणी "बी"
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल धूसड़, गोरखपुर
स्थापित २००५ ई.
7897475917, 9794299451
Website: www.mpm.edu.in
E-mail : mpmpg5@gmail.com

पत्रांक..... दिनांक :29.08.2020

प्रकाशनार्थ

(अन्तर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी का उद्घान एवं प्रथम तकनीकी सत्र)

महाराणा प्रताप पी.जी. कालेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर के राजनीतिशास्त्र विभाग के तत्वावधान में **"भारत की पड़ोसी नीति : सामयिक राजनयिक विमर्श"** विषय पर आयोजित **दो दिवसीय ऑनलाइन अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी** के उद्घाटन अवसर पर बीजवक्तव्य प्रस्तुत करते हुए **पूर्व निदेशक यशवन्त राव चव्हाण राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा विश्लेषण केन्द्र, महाराष्ट्र, रक्षा एवं राजनयिक मामलो के विशेषज्ञ प्रो. गौतम सेन** ने कहा कि शान्तिपूर्ण विदेश नीति के साथ रणनीतिक और राजनयिक स्तर पर भी सजकता का परिचय देना होगा। राष्ट्रीय स्थिरता और अखण्डता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति तथा पड़ोसी राज्यों के साथ हमारे सम्बन्धों में शान्ति और स्थिरता लाने का प्रयास होना चाहिए। इसलिए तीन आयामों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और संस्थागत कौशल तथा बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता है। यह राष्ट्र के नेतृत्त्व पर निर्भर करता है कि प्रत्येक राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रर्याप्त संसाधन और अवसर पैदा करें। विश्व स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर गतिशील और व्यवाहरिक नेतृत्त्व के द्वारा प्रभावी विदेश नीति के माध्यम से वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए हम समाधान की तरफ बढ़ सकते है। इस परिप्रेक्ष्य में आर्थिक निर्णय बहुत ही प्रभावशाली होते है। प्रो. गौतम सेन ने आगे कहा कि राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पड़ोसियों में जो उलट फेर होता है वह कोई नयी बात नहीं है। भारत की पड़ोस नीति का सांस्कृतिक और नृजातीय पहलू सदैव से इसे एक–दूसरे से जोड़ कर रखे हुए है। **राजनयिक स्तर पर यह देखा जाता था कि भारत रक्षात्मक नीति का अनुसरण करता रहा किन्तु अब इस सन्दर्भ में दिल्ली की सक्रिय सहभागिता बड़ी है और गतिशील विदेश नीति की तरफ उन्मुख हुई है।**

संगोष्ठी के प्रथम सत्र में **"भारत–पकिस्तान सम्बन्ध : चुनौतिया एवं समाधान के विविध आयाम"** अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए **मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली के सीनियर फेलो डॉ. अशोक बहुरिया** ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध काफी नाजुक दौर से गुजरे है और यह एक बिट्र–स्वीट वाला रिश्ता रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखे तो भारत–पाकिस्तान के बीच जो भी द्विपक्षीय समझौते हुए उसने अपनी प्रभावपूर्ण प्रसंगिकता नहीं दिखाई। भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ रिश्तों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान द्वारा भारत से समझौते के जो भी राजनीतिक प्रयास किये गये उसे पाकिस्तानी सेना द्वारा ठुकराया जाता रहा, ऐसे में दोनों के बीच अविश्वास की स्थिति सदैव बनी दिखाई देती है। भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध को सुधारने के लिए होने वाले संवाद में भारत ने हमेशा मजबूती के साथ जम्मू–कश्मीर विषय को अपना आन्तरिक मामला बताया है और अब जब अनुच्छेद 370 और 35 ए निष्प्रभावी हो गये है तब भारत का यह पक्ष स्वयं सिद्ध हो जाता है। पाक प्रायोजित आतंकवाद और घुसपैठ का मुद्दा भी भारत की तरफ से उठाये जाने पर पाकिस्तान द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है। वह दोनों देशों के बीच सम्बन्ध को बेपटरी (डीरेल) कर देती है। वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा **नेबरहुड फर्स्ट पालिसी** को आगे बढ़ाते हुए उसे बिम्सटेक के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, और इसकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। हमे सदैव यह याद रखना चाहिए कि यदि हम अपने पड़ोसी नही बदल सकते तो हमें उनके साथ बैठकर समस्याओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ना होगा। भारत के पड़ोसी देशो की भौगोलिक एकता का दक्षिण एशिया में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

विशेष वक्ता के रूप में **कराची विश्वविद्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय मामलो के विशेषज्ञ प्रो. श्रीमती नौशीन वासी** ने कहा कि दोनो मुल्को के अवाम के बीच मुहब्बत बहुत है लेकिन दोनो देशो में सक्रिय अतिवादी वैचारिकी ने रिश्तो को जटिल कर दिया है। पाकिस्तानी राजनय दोनो देशों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना चाहता है किन्तु सेना द्वारा हस्तक्षेप के कारण स्थितियाँ उलट जाती है। पाकिस्तान अभी भी उत्तर उपनिवेशवाद के प्रभाव से

अभी भी उभर नहीं पाया है इसकारण से आज तक पाकिस्तान की कोई स्वतंत्र विदेश नीति नही बन पायी। पाकिस्तान की विदेश नीति ज्यादातर स्थानीय आंतरिक मुद्दो से प्रभावित रहती है। विश्व की बड़ी ताकते दोनों देशों के बीच बेहतर सम्बन्धों को प्रोन्नत न करके अपने राष्ट्रीय हितो को साधने का प्रयास करती रही है। वर्तमान में अफगानिस्तान की जो स्थितियाँ है उससे भी पाकिस्तानी अतिवादियों को एक बड़ी खुराक मिल रही है। हमें यह समझना होगा कि दक्षिण एशिया में भारत–पाकिस्तान की स्थिति को कोई भी शक्ति अनदेखा नहीं कर सकती।

मुम्बई विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र के विषय विशेषज्ञ प्रो. लियाकत खान ने कहा कि भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों में सच्चाई का कम मिथक का अधिक ध्यान दिया जाता है। हमें बौद्धिक विश्लेषण के साथ–साथ भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों में भावनाओं को भी स्थान देना होगा। भारत–पाकिस्तान के बीच व्यापारिक सम्बन्धों के हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। कृषि, सिचाई, आवागमन और यातायात ने भारत–पाक को एक दूसरे से भौगोलिक स्तर पर जोड़कर रखा है। भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों को राज्येत्तर कर्ताओं ने भी प्रभावित किया है। हमें सदैव इस सजगता के साथ भारत–पाकिस्तान के सम्बन्धों को देखना होगा कि कोई भी तीसरी ताकत हस्तक्षेप न कर सके। हमें शान्तिपूर्ण अन्योन्याश्रित और सहकारी कार्यो की स्थापना के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से एक–दूसरे के प्रति अविश्वास को कम कर के देखना होगा। भारत क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा है।

इससे पूर्व संगोष्ठी की विषय प्रस्तावना रखते हुए **समन्वयक सीएसएसईआईपी, राजनीति विज्ञान विभाग, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रो. तेज प्रताप सिंह** ने कहा कि भारत के प्रभुत्वशाली आकार और क्षमताओं साझा ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्कों ने हमेशा ही इसके पड़ोसियों के बीच पहचान के संकट की भावना पैदा की है जिसमें भारत–विरोधी भावनाओं का उभार हुआ है। सामाजिक सन्दर्भ एवं परिस्थितियों में जब पूरा विश्व कोविड–19 नामक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को नए सिरे से परिभाषित करने का एक सुअवसर और देश की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' की प्रासंगिकता को बहाल करने की एक चुनौती है। नेपाल के साथ भी भारत के अच्छे सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं, परन्तु नेपाल की आन्तरिक स्थिति तथा यहा चीन की मौजूदगी सम्बन्धों को प्रभावित कर रही है। बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ संबंध तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन चीन की मौजूदगी यहां भी सम्बन्धों को प्रभावित कर रही है। भूटान के साथ भारत के सदैव मैत्रीपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं तथा वर्तमान में भी वे सम्बन्ध प्रगतिशील हैं। अपनी सामरिक आवश्यकताओं को साधने के साथ ही दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व की स्थापना; आर्थिक विकास, व्यापारिक उन्नति, आसियान देशो के क्षेत्रों के विकास एवं सीमा प्रबन्धन में इन देशों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि भारत अपनी नीति में पड़ोसी देशों को प्राथमिकता एवं वरीयता प्रदान करें।

भारत–पाकिस्तान के सम्बन्धों का इतिहास असहमति की बाढ़ एवं सहमति के अकाल का इतिहास रहा है। इसका विकास एक कदम आगे और दो कदम पीछे के रूप में हुआ है। सह–सामयिक विश्व में एक ही भौगोलिक इकाई के दो राष्ट्रो के बीच परस्पर तीव्र राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विरोध एवं संघर्ष रहा है। कोरिया, वियतनाम, जर्मनी, फिलीस्तीन सभी इसी सामान्य कोटि में आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता एवं संघर्ष इस सामान्य परिदृश्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन एक ही भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रतिरक्षा इकाई का विभाजन है जिसके कारण स्वाभाविक विसंगतियों, त्रुटियों एवं अनौचित्यों का प्रभाव रहा है। भौगोलिक निकटता, खुली सीमा, सांस्कृतिक सभ्यता, ऐतिहासिक और सामाजिक बन्धनों ने भारत और नेपाल के बीच प्राचीन काल से लेकर अब तक अंतरंगता बनाये रखा है। खुली सीमा, व्यापार एवं पारगमन से सम्बन्धित मसलों ने नेपाल में भारत–विरोधी भावना को जगाया है और नेपाल ने अक्सर हीं भारत के रोबीले प्रभाव

से अपने को मुक्त करने के लिए चीन कार्ड का प्रयोग किया। सामयिक सन्दर्भ की अनेक घटनायें इसका ज्वलंत उदाहरण कभी–कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि भारत की अदूरदर्शिता से नेपाल–चीन के पाले में दिखायी दे रहा है। नेपाल में चीन की उपस्थिति पर भारत सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा महसूस कर सकता है, भारत को इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।

संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर स्वागत उद्बोधन देते हुए **महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार राव** ने कहा कि यह सत्य है कि भारत महामारी से उतना ही त्रस्त है, जितना कि दक्षिण एशिया के अन्य देश। यदि ऐसी स्थिति में कुछ भिन्न है तो यह कि पश्चिम देशों की तुलना में भारत इस महामारी से निपटने में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यदि भारत कोविड–19 महामारी के प्रबन्धन में वर्तमान स्थिति को बनाए रखता है तो इस बात की पूरी सम्भावना है कि नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त होकर उभरेगी। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाये रखने हेतु थ्री सी (कल्चर, कामर्स कनेक्तिनिती) को बढ़ावा देना होगा। इस संकट की घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देशों को दवाइयां व अन्य चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध करा सकता है, इससे भारत के 'साफ्ट पावर नीति में वृद्धि होगी।

ऑनलाईन अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का संचालन संयोजक डॉ. अविनाश प्रताप सिंह तथा आभार ज्ञापन आयोजन सचिव डॉ. कृष्ण कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में गोवा विश्वविद्यालय से प्रो. राहुल मणि त्रिपाठी, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से प्रो. जी.राम रेड्डी सहित देश और दुनिया के अनेक विद्वान और रिर्सच स्कालर इस वेबीनार में सम्मलित हुए।

(डॉ. अविनाश प्रताप सिंह)
संगोष्ठी, संयोजक